20

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 5–3/2006/1/3 भोपाल, दिनांक 16 मई, 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्य प्रदेश ।

विषयः मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक अपील (सिविल) 3595–3612/1999, सचिव कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरूद्ध उमादेवी एवं अन्य के प्रकरण में दिनांक 10.04.2006 को पारित निर्णय में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार दैनिक वेतन भोगियों, अस्थायी कर्मचारियों के प्रकरण में कार्यवाही बाबत्।

सन्दर्भः सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्र. एफ 5–3/2004/एक/3, भोपाल, दिनांक 12.4.2005 ।

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 3492/1996 हिमांचल प्रदेश सरकार विरूद्ध सुरेश कुमार वर्मा के प्रकरण में दी गई व्यवस्था अनुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, श्रमिकों के सिविल पदों एवं सेवाओं में नियमितीकरण पर रोक लगाकर नियमितीकरण के संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त निर्देशों/आदेशों को निरस्त किया गया है।

2/ मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक अपील (सिविल) 3595–3612/1999, सचिव कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरूद्ध उमादेवी एवं अन्य के प्रकरण में दिनांक 10.04.2006 को निर्णय पारित कर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। आदेश के मुख्य अंशों की जानकारी परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। मा. **सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जावे। इस प्रकरण में दी गई व्यवस्था अनुसार विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में प्रतिरक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। मा. सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ण आदेश http://supremecourtofindia. nic.in/ वेबसाईट पर उपलब्ध है, तथा (2006) 4 scc1** पर प्रकाशित है।

3/ मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार राज्य सरकार एवं इनके नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी **केवल एक ही बार के लिए** 10 वर्षो या अधिक से **नियमानुसार स्वीकृत पदों** पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/अस्थाई कर्मचारियों की **अनियमित नियुक्तियों** (Irregular appointments) को **{(अवैधानिक नियुक्तियों** (Illegal appointments) **को नही)}** नियमित करने की कार्यवाही की जानी चाहिए। न्यायालय अथवा प्रशासनिक अधिकरण के आदेश से कार्यरत कर्मचारियों को इस प्रकार के नियमितीकरण की पात्रता नहीं होगी। वर्तमान में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्वीकृत नियमित पदों, जहां पर अस्थाई कर्मचारी अथवा दैनिक वेतन भोगी भर्ती किए जा रहे हैं, वहां पर केवल भर्ती नियमों के अनुसार ही नियमित नियुक्ति की कार्यवाही की जावे। **भविष्य में नियमितीकरण एवं स्थाई सेवा में लिए जाने के लिए संवैधानिक आवश्यकताओं एवं संविधान की मंशानुसार किए गए प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।** मा. सर्वोच्च न्यायालय व्दारा यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई नियमितीकरण पूर्व में किया गया है एवं न्यायालयों में विचाराधीन नहीं है, ऐसे प्रकरणों को मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में पुनः परीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

4.1/ **अवैधानिक नियुक्ति** से तात्पर्य है कि – "संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत अपात्र लोगों की, ऐसी कार्यवाही के अंतर्गत की गई नियुक्ति जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो तथा ऐसी नियुक्ति करने हेतु नियुक्तिकर्ता वैध रूप से आबद्ध न हो तथा ऐसी नियुक्ति करना अवैधानिक हो तथा ऐसी नियुक्ति के लिए पद स्वीकृत नहीं होते हुए या नियुक्तिकर्त्ता को नियुक्ति के अधिकार नहीं होते हुए नियम/बाध्यकारी प्रावधानों के उल्लंघन में की गई हो।" उदाहरणार्थ –

- पद स्वीकृत न होना
- आरक्षण नियमों का उल्लंघन कर की गई भर्ती।
- नियुक्ति के समय निर्धारित आयु सीमा न होना।
- भर्ती नियम अनुसार अर्हता न होना।
- नियुक्ति के अधिकार के बिना नियुक्ति।
- कोई पद पर नियुक्ति विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, फिर भी ऐसे नियमों या संविधान के आज्ञापक प्रावधानों के उल्लंघन में भर्ती की गई हो।

यह सूची उदाहरणस्वरूप है न कि पूर्ण है।

4.2/ **अनियमित नियुक्ति** से तात्पर्य है – "ऐसी नियुक्ति जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 तथा 309 के अंतर्गत किसी राज्य द्वारा नियुक्ति हेतु निर्मित नियमों में से किसी ऐसे नियम से हटकर नियुक्ति दी गई हो जो मूल आधार को प्रभावित

नहीं करता हो या नियमों के अभाव में प्रक्रिया अपनाए बिना या भर्ती के प्रक्रियागत नियमों का पालन किए बगैर की गई हो। प्रकिया का पालन किए बगैर जो नियुक्ति की गई हो वह अनियमित नियुक्ति की श्रेणी में आएगी। अर्थात् नियुक्त किया गया व्यक्ति पात्र तो है लेकिन भर्ती की कोई एक–दो तरह की सामान्य प्रकिया नहीं अपनाने से ऐसी भर्ती अनियमित नियुक्ति कहलाएगी।"

किसी पद पर नियुक्ति हेतु आधारभूत अर्हताओं को प्रभावित किए बगैर, सक्षम प्राधिकारी व्दारा किसी प्रकियागत नियमों का पालन किए बगैर स्वीकृत रिक्त पद के उपलब्ध होने पर अस्थायी, संविदा नियुक्ति अथवा किसी विशेष कार्य/योजना के निमित्त दैनिक वेतन पर अस्थायी नियुक्ति, संविदा नियुक्ति, स्थानापन्न नियुक्ति, उस पद के लिए वांछित पात्रता रखने वाले व्यक्ति को नियुक्ति दी हो तो वह अनियमित नियुक्ति कहलायेगी। उदाहरणार्थ–

- किसी प्रकियागत नियमों का उल्लंघन किया जाना जो मूलभूत आधार को प्रभावित न करता हो
- किसी नियम मात्र का उल्लंघन किया हो जो प्रकियागत ऐसी त्रुटि न हो कि मूल आधार को ही प्रभावित करती हो।

5/ पैरा –3 के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित पत्र में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है एवं निम्नानुसार कार्यवाही **केवल एक ही बार के लिए** सुनिश्चित की जावे :–

5.1 दिनांक 10.04.2006 की स्थिति में प्रत्येक विभाग के अधीन विभागाध्यक्ष द्वारा **मा. सर्वोच्च न्यायालय एवं उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर** ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाई जाकर पैरा 5.2 अनुसार **छानबीन समिति को प्रस्तुत की जावे, जो–**

- 10 वर्ष से अधिक से निरंतर सेवारत हैं किंतु इनमें ऐसे व्यक्ति शामिल नहीं किए जावें, जो न्यायालय/न्यायिक अधिकरण के आदेश से कार्यरत हों,
- जिन्हें स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध रखा गया है,
- जिस पद पर रखा गया है उस पद की भर्ती नियमों के अनुसार अर्हता रखता हो,
- जिस समय रखा गया उस समय शासन के आदेशानुसार निर्धारित आयु सीमा हो,
- जिसकी नियुक्ति भर्ती नियमों अनुसार सक्षम प्राधिकारी व्दारा की गई हो,
- जिस वर्ग (अजा/अजजा/पिछड़ वर्ग/अनारक्षित) का रिक्त पद है वह उसी वर्ग से संबंधित हो,

- जो अभी न्यायालयीन स्थगन के आधार पर सेवारत न हो।
- **विभागाध्यक्ष की यह जिम्मेदारी होगी कि यह सूची मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एवं उक्त निर्देशों के अनुरूप हो।**

5.2 संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में प्रत्येक विभाग द्वारा एक छानबीन समिति गठित की जावे, (जिसमें संबंधित विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव/सचिव के मत में आवश्यक होने पर अन्य अधिकारियों) तथा सामान्य प्रशासन, वित्त एवं विधि विभाग के प्रतिनिधि को सदस्य रखा जावे। यह समिति पैरा–3 से पैरा–5 के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में ऐसे प्रकरणों की छान–बीन करेगी जो विभागाध्यक्ष व्दारा पैरा– 5.1 अनुसार प्रस्तुत किये जायेंगे।

5.3 **नीचे उल्लेखित कंडिका–12 की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत** छानबीन समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं पर संबंधित पद के नियुक्तिकर्ता अधिकारी व्दारा नियमितीकरण की कार्यवाही की जावेगी। **यह नियमितीकरण जारी आदेश दिनांक से प्रभावशील होगा। पूर्व की सेवा, पेंशन एवं अन्य स्वत्वों के लिए इस हेतु मान्य नहीं होगी। नियमितीकरण होने पर नियमितीकण के आदेश के दिनांक से संबंधित पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन से वेतनमान आरंभ होगा।**

5.4 छानबीन समिति यह सुनिश्चित करेगी कि नियमितीकरण केवल अनियमित नियुक्त (Irregular Appointed) का ही किया जावे एवं यह सुनिश्चित किया जावेगा कि अवैधानिक नियुक्त (Illegal Appointed) पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

5.5 नियमितीकरण नियमानुसार स्वीकृत नियमित पद, जिस वर्ग के लिए रिक्त है एवं जिसके विरूद्ध उसी संवर्ग का दैनिक वेतन भोगी एवं अस्थाई कर्मचारी जो 10 वर्ष या अधिक से कार्यरत हैं, पर ही किया जाना है, अन्य पर नहीं। जो पद भर्ती नियम में संविदा नियुक्ति अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु उपलब्ध है उन पर नियमितीकरण नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार नियमितीकरण के लिए शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति का ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए विभागाध्यक्ष एवं नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

5.6 10 वर्षों की सेवा की गणना में उन दैनिक वेतनभोगी/अस्थायी कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जावे, जिनका न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा सेवारत रखे जाने का आदेश पारित किया गया है, एवं प्रकरण अभी विचाराधीन है।

5.7 दैनिक वेतन भोगी एवं अस्थाई कर्मचारी लंबी अवधि से कार्य कर रहे हैं एवं सामान्यतः इन कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन भी नहीं रखे जाते हैं, जिसके आधार पर इनके कार्य का मूल्यांकन किया जा सके। ऐसी स्थिति में कोई

लिखित परीक्षा या साक्षात्कार लेने की आवश्यकता नहीं है। चयन सूचियां यह मानकर तैयार की जावें कि इनका कार्य संतोषजनक रहा है, बशर्ते कि संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध कोई आपत्तिजनक स्थिति प्रकाश में नहीं आई हो। आपत्तिजनक स्थिति ध्यान में आने पर नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं की जावे।

5.8 संबंधित पद की नियुक्ति के लिए नियमों में निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं अनिवार्य होगी। जिन व्यक्तियों के पास निर्धारित योग्यताएं नहीं हैं, उन पर विचार नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह नियुक्ति आरंभ से ही अवैधानिक है।

5.9 उपरोक्तानुसार नियमित व्यक्ति की विभाग में ज्येष्ठता नियमितीकरण के आदेश की तारीख से मानी जाएगी अर्थात उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा, जो ऐसे व्यक्ति को नियमित नियुक्ति किए जाने के पूर्व सुसंगत भरती नियमों के अनुसार नियमित रूप से नियुक्त किया गया था।

5.10 वरिष्ठताक्रम निर्धारित करते समय यदि 2 व्यक्तियों की सेवा अवधि समान हो तो उनमें से जो आयु में अधिक होगा उसको वरिष्ठ माना जावेगा।

5.11 भविष्य में भर्ती नियमों के अनुसार नियमित पदों पर केवल नियमित नियुक्ति ही की जावे। नियमित पदों पर दैनिक वेतन भोगी/संविदा आदि से नियुक्ति न की जावे।

5.12 भविष्य में कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी की अस्थायी या संविदा नियुक्ति किसी विशेष कार्य हेतु, समय विशेष के लिए भी आकस्मिक नियुक्ति, करना हो तो भी भर्ती के सभी आवश्यक नियमों का पालन करते हुए ही भर्ती की जावे, जिससे सभी योग्य लोगों को प्रतिस्पर्द्धा का मौका मिल सके।

6/ समस्त विभागाध्यक्ष द्वारा इन निर्देशों की प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस की समय सीमा में पैरा 5.1 अनुसार दैनिक वेतन भोगी/अस्थाई कर्मचारियों की सूची विभागीय छानबीन समिति को प्रस्तुत की जावेगी।

7/ समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष द्वारा छानबीन समिति को सूची प्रस्तुत होने के पश्चात् 15 दिवस की अवधि में छानबीन समिति प्रस्तुत सूची पर इन निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अपना अभिमत देना सुनिश्चित करें।

8/ **उपरोक्त पैरा–7 अनुसार तैयार की गई विभागाध्यक्षवार इकजायी जानकारी समस्त विभाग दिनांक 30 जून, 2007 तक सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष–3) को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।**

9/ सभी विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि उक्त कार्यवाही समयसीमा में पूर्ण कर ली गई है। **उपरोक्तानुसार कार्यवाही केवल एक समय के लिए सुनिश्चित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभागों की होगी।**

10/ मा. सर्वोच्च न्यायालय व्दारा शासन के नियंत्रणाधीन स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी के व्दारा भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव उनके नियंत्रणाधीन स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी स्तर पर मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु विभागीय स्तर से निर्देश जारी करेंगे एवं इस हेतु इन संस्थाओं के अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करेंगे, ताकि सर्वोच्च न्यायालय का इन संस्थाओं में पालन हो सके। इसके लिए विभाग स्तर पर 5.2 के अनुसार छानबीन समिति प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित की जावे।

11/ परिपत्र की कंडिका–8 की जानकारी प्रपत्र "एक" में तथा कंडिका– 10 की जानकारी प्रपत्र "दो" में प्रेषित की जाए।

12/ विभागों से निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्राप्त होने पर समग्र स्थिति मंत्रि–परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। मंत्रि–परिषद निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आगामी कार्यवाही हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जावेगें। **इसके पूर्व कोई भी विभाग/नियुक्ति प्राधिकारी नियमितीकरण के आदेश जारी नहीं करेंगे।**

(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क0 एफ. 5–3/2006/1/3 भोपाल, दिनांक 16 मई, 2007

प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र., जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र., भोपाल
3. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र., भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म.प्र., भोपाल
8. मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र., भोपाल

9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र., भोपाल
10. सचिव, म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म.प्र.उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर /जबलपुर
13. महालेखाकार, म.प्र., ग्वालियर/भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सा.प्र.वि., मंत्रालय, भोपाल
15. उप सचिव/ अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण / अभिलेख /मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय, भोपाल
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, म.प्र., भोपाल
18. अध्यक्ष, म.प्र.राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(आर0के0 गजभिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

परिशिष्ट–1

CASE NO.:
Appeal (civil) 3595-3612 of 1999

PETITIONER:
Secretary, State of Karnataka and others

RESPONDENT:
Umadevi and others

DATE OF JUDGMENT: 10/04/2006

BENCH:
Y.K. SABHARWAL ARUN KUMAR G.P. MATHUR, C.K. THAKKER & P.K. BALASUBRAMANYAN

JUDGMENT:
J U D G M E N T

WITH
CIVIL APPEAL NO.1861-2063/2001, 3849/2001.
3520-3524/2002 and CIVIL APPEAL NO. 1968 of 2006
arising out of SLP(C)9103-9105 OF 2001

P.K. BALASUBRAMANYAN, J.

Leave granted in SLP(C) Nos.9103-9105 of 2001

1. Public employment in a sovereign socialist secular democratic republic, has to be as set down by the Constitution and the laws made thereunder. Our constitutional scheme envisages employment by the Government and its instrumentalities on the basis of a procedure established in that behalf. Equality of opportunity is the hallmark, and the Constitution has provided also for affirmative action to ensure that unequals are not treated equals. Thus, any public employment has to be in terms of the constitutional scheme.

2. A sovereign government, considering the economic situation in the country and the work to be got done, is not precluded from making temporary appointments or engaging workers on daily wages..... But, a regular process of recruitment or appointment has to be resorted to, when regular vacancies in posts, at a particular point of time, are to be filled up and the filling up of those vacancies cannot be done in a haphazard manner or based on patronage or other considerations. Regular appointment must be the rule.

But, sometimes this process is not adhered to and the Constitutional scheme of public employment is by-passed..... It has also led to persons who get employed, without the following of a regular procedure or even through the backdoor or on daily wages, approaching Courts, seeking directions to make them permanent in their posts and to prevent regular recruitment to the concerned posts. Courts have not always kept the legal aspects in mind and have occasionally even stayed the regular process of employment being set in motion and in some cases, even directed that these illegal, irregular or improper entrants be absorbed into service. A class of employment which can only be called 'litigious employment', has risen like a phoenix seriously impairing the constitutional scheme..... It is time, that Courts desist from issuing orders preventing regular selection or recruitment at the instance of such persons and from issuing directions for continuance of those who have not secured regular appointments as per procedure established. The passing of orders for continuance, tends to defeat the very Constitutional scheme of public employment. It has to be emphasized that this is not the role envisaged for High Courts in the scheme of things and their wide powers under Article 226 of the Constitution of India are not intended to be used for the purpose of perpetuating illegalities, irregularities or improprieties or for scuttling the whole scheme of public employment. Its role as the sentinel and as the guardian of equal rights protection should not be forgotten.

4. This Court has also on occasions issued directions which could not be said to be consistent with the Constitutional scheme of public employment. Such directions are issued presumably on the basis of equitable considerations or individualization of justice. The question arises, equity to whom? Equity for the handful of people who have approached the Court with a claim, or equity for the teeming millions of this country seeking employment and seeking a fair opportunity for competing for employment? When one side of the coin is considered, the other side of the coin, has also to be considered and the way open to any court of law or justice, is to adhere to the law as laid down by the Constitution and not to make directions, which at times, even if do not run counter to the Constitutional scheme, certainly tend to water down the Constitutional requirements. It is this conflict that is reflected in these cases referred to the Constitution Bench.

10. .....The States have made Acts, Rules or Regulations for implementing the above constitutional guarantees and any recruitment to the service in the State or in the Union is governed by such Acts, Rules and Regulations. The Constitution does not envisage any employment outside this constitutional scheme and without following the requirements set down therein.

11. In spite of this scheme, there may be occasions when the sovereign State or its instrumentalities will have to employ persons, in posts which are temporary, on daily wages, as additional hands or taking them in without following the required procedure, to discharge the duties in respect of the posts that are sanctioned and that are required to be filled in terms of the relevant procedure established by the Constitution or for work in temporary posts or projects that are not needed permanently. This right of the Union or

of the State Government cannot but be recognized and there is nothing in the Constitution which prohibits such engaging of persons temporarily or on daily wages, to meet the needs of the situation. But the fact that such engagements are resorted to, cannot be used to defeat the very scheme of public employment. Nor can a court say that the Union or the State Governments do not have the right to engage persons in various capacities for a duration or until the work in a particular project is completed. Once this right of the Government is recognized and the mandate of the constitutional requirement for public employment is respected, there cannot be much difficulty in coming to the conclusion that it is ordinarily not proper for courts whether acting under Article 226 of the Constitution or under Article 32 of the Constitution, to direct absorption in permanent employment of those who have been engaged without following a due process of selection as envisaged by the constitutional scheme.

12. ..... It cannot also be forgotten that it is not the role of courts to ignore, encourage or approve appointments made or engagements given outside the constitutional scheme. In effect, orders based on such sentiments or approach would result in perpetuating illegalities and in the jettisoning of the scheme of public employment adopted by us while adopting the Constitution. The approving of such acts also results in depriving many of their opportunity to compete for public employment.

13. ..... Learned counsel for the State of Karnataka submitted that chaos has been created by such orders without reference to legal principles and it is time that this Court settled the law once for all so that in case the court finds that such orders should not be made, the courts, especially, the High Courts would be precluded from issuing such directions or passing such orders. ..... It is necessary to put an end to uncertainty and clarify the legal position emerging from the constitutional scheme, leaving the High Courts to follow necessarily, the law thus laid down.

14. Even at the threshold, it is necessary to keep in mind the distinction between regularization and conferment of permanence in service jurisprudence. In STATE OF MYSORE Vs. S.V. NARAYANAPPA [1967 (1) S.C.R. 128], this Court stated that it was a mis-conception to consider that regularization meant permanence. In R.N. NANJUNDAPPA Vs T. THIMMIAH & ANR. [(1972) 2 S.C.R. 799], this Court dealt with an argument that regularization would mean conferring the quality of permanence on the appointment. This Court stated:-

"Counsel on behalf of the respondent contended that regularization would mean conferring the quality of permanence on the appointment, whereas counsel on behalf of the State contended that regularization did not mean permanence but that it was a case of regularization of the rules under Article 309. Both the contentions are fallacious. If the appointment itself is in infraction of the rules or if it is in violation of the provisions of the Constitution, illegality cannot be regularized. Ratificatio.. or regularization is possible of an act which is within the power and province of the authority, but there has been some non-compliance with procedure or manner which does not go to the root of the appointment. Regularization cannot be said to be a mode of recruitment. To accede to such a proposition would be to introduce a new head of appointment in defiance of rules

or it may have the effect of setting at naught the rules." In B.N. Nagarajan & Ors. V. State of Karnataka & Ors. [(1979) 3 SCR 937], this court clearly held that the words "regular" or "regularization" do not connote permanence and cannot be construed so as to convey an idea of the nature of tenure of appointments. They are terms calculated to condone any procedural irregularities and are meant to cure only such defects as are attributable to methodology followed in making the appointments. This court emphasized that when rules framed under Article 309 of the Constitution of India are in force, no regularization is permissible in exercise of the executive powers of the Government under Article 162 of the Constitution in contravention of the rules. These decisions and the principles recognized therein have not been dissented to by this Court and on principle, we see no reason not to accept the proposition as enunciated in the above decisions. We have, therefore, to keep this distinction in mind and proceed on the basis that only something that is irregular for want of compliance with one of the elements in the process of selection which does not go to the root of the process, can be regularized and that it alone can be regularized and granting permanence of employment is a totally different concept and cannot be equated with regularization.

15. ..... This right of the executive and that of the court, would not extend to the executive or the court being in a position to direct that an appointment made in clear violation of the constitutional scheme, and the statutory rules made in that behalf, can be treated as permanent or can be directed to be treated as permanent.

17. One aspect arises. Obviously, the State is also controlled by economic considerations and financial implications of any public employment. The viability of the department or the instrumentality or of the project is also of equal concern for the State. The State works out the scheme taking into consideration the financial implications and the economic aspects. Can the court impose on the State a financial burden of this nature by insisting on regularization or permanence in employment, when those employed temporarily are not needed permanently or regularly?..... So, the court ought not to impose a financial burden on the State by such directions, as such directions may turn counter-productive.

19. .....The Court appears to have been dealing with a scheme for 'equal pay for equal work' and in the process, without an actual discussion of the question, had approved a scheme put forward by the State, prepared obviously at the direction of the Court, to order permanent absorption of such daily rated workers. With respect to the learned judges, the decision cannot be said to lay down any law, that all those engaged on daily wages, casually, temporarily, or when no sanctioned post or vacancy existed and without following the rules of selection, should be absorbed or made permanent though not at a stretch, but gradually. If that were the ratio, with respect, we have to disagree with it.

23. ..... in connection with particular project, on completion of that work or of that project, those who were temporarily engaged or employed in that work or project

could not claim any right to continue in service and the High Court cannot direct that they be continued or absorbed elsewhere.

24. ..... Appointment on daily wage basis is not an appointment to a post according to the Rules." Their Lordships cautioned that if directions are given to re-engage such persons in any other work or appoint them against existing vacancies, "the judicial process would become another mode of recruitment dehors the rules."

29. .....there was no power in the State under Art. 162 of the Constitution of India to make appointments and even if there was any such power, no appointment could be made in contravention of statutory rules. This Court also held that past alleged regularisation or appointment does not connote entitlement to further regularization or appointment. It was further held that the High Court has no jurisdiction to frame a scheme by itself or direct the framing of a scheme for regularization.

34- .....Therefore, consistent with the scheme for public employment, this Court while laying down the law, has necessarily to hold that unless the appointment is in terms of the relevant rules and after a proper competition among qualified persons, the same would not confer any right on the appointee. If it is a contractual appointment, the appointment comes to an end at the end of the contract, if it were an engagement or appointment on daily wages or casual basis, the same would come to an end when it is discontinued. Similarly, a temporary employee could not claim to be made permanent on the expiry of his term of appointment. It has also to be clarified that merely because a temporary employee or a casual wage worker is continued for a time beyond the term of his appointment, he would not be entitled to be absorbed in regular service or made permanent, merely on the strength of such continuance, if the original appointment was not made by following a due process of selection as envisaged by the relevant rules. It is not open to the court to prevent regular recruitment at the instance of temporary employees whose period of employment has come to an end or of ad hoc employees who by the very nature of their appointment, do not acquire any right. High Courts acting under Article 226 of the Constitution of India, should not ordinarily issue directions for absorption, regularization, or permanent continuance unless the recruitment itself was made regularly and in terms of the constitutional scheme. Merely because, an employee had continued under cover of an order of Court, which we have described as 'litigious employment' in the earlier part of the judgment, he would not be entitled to any right to be absorbed or made permanent in the service. In fact, in such cases, the High Court may not be justified in issuing interim directions, since, after all, if ultimately the employee approaching it is found entitled to relief, it may be possible for it to mould the relief in such a manner that ultimately no prejudice will be caused to him, whereas an interim direction to continue his employment would hold up the regular procedure for selection or impose on the State the burden of paying an employee wl.. is really not required. The courts must be careful in ensuring that they do not interfere unduly with the economic arrangement of its affairs by the State or its instrumentalities or lend themselves the instruments to facilitate the bypassing of the constitutional and statutory mandates.

39. .... Those who are working on daily wages formed a class by themselves, they cannot claim that they are discriminated as against those who have been regularly recruited on the basis of the relevant rules. No right can be founded on an employment on daily wages to claim that such employee should be treated on a par with a regularly recruited candidate, and made permanent in employment, even assuming that the principle could be invoked for claiming equal wages for equal work. There is no fundamental right in those who have been employed on daily wages or temporarily or on contractual basis, to claim that they have a right to be absorbed in service.

40. ....It is therefore not possible to accept the argument that there must be a direction to make permanent all the persons employed on daily wages. When the court is approached for relief by way of a writ, the court has necessarily to ask itself whether the person before it had any legal right to be enforced.

44. One aspect needs to be clarified. There may be cases where irregular appointments (not illegal appointments) as explained in S.V. NARAYANAPPA (supra), R.N. NANJUNDAPPA (supra), and B.N. NAGARAJAN (supra), and referred to in paragraph 15 above, of duly qualified persons in duly sanctioned vacant posts might have been made and the employees have continued to work for ten years or more but without the intervention of orders of courts or of tribunals. The question of regularization of the services of such employees may have to be considered on merits in the light of the principles settled by this Court in the cases above referred to and in the light of this judgment. In that context, the Union of India, the State Governments and their instrumentalities should take steps to regularize as a one time measure, the services of such irregularly appointed, who have worked for ten years or more in duly sanctioned posts but not under cover of orders of courts or of tribunals and should further ensure that regular recruitments are undertaken to fill those vacant sanctioned posts that require to be filled up, in cases where temporary employees or daily wagers are being now employed. The process must be set in motion within six months from this date. We also clarify that regularization, if any already made, but not subjudice, need not be reopened based on this judgment, but there should be no further by-passing of the constitutional requirement and regularizing or making permanent, those not duly appointed as per the constitutional scheme.

45. It is also clarified that those decisions which run counter to the principle settled in this decision, or in which directions running counter to what we have held herein, will stand denuded of their status as precedents.

—— x ——

प्रपत्र "एक"

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 5–3/2006/1/3 दिनांक 14/5/2007 क अनुपालन में छानबीन समिति द्वारा अनुशंसित जानकारी.

1. विभाग का नाम.....

2. विभागाध्यक्ष का नाम .....

क.	पदनाम	विभाग में कुल दैनिक वेतनभोगी/ अस्थाई/ संविदा नियुक्तियों की संख्या	कॉलम (3) में 10 वर्ष से अधिक की अवधि से निरन्तर कार्यरत की संख्या	समिति द्वारा नियमितीकरण हेतु उपयुक्त पाये गये प्रकरणों की संख्या	नियमितीकरण हेतु शेष बचे कर्मचारियों की संख्या. (कॉलम नं. 3–4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.

अधिकारी का नाम एवं पदनाम

प्रपत्र "दो"

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 5–3/2006/1/3 दिनांक 14/5/2007 के अनुपालन में छानबीन समिति द्वारा अनुशंसित जानकारी.

1. विभाग का नाम.....

2. स्थानीय संस्था/निगम/मण्डल/बोर्ड/आयोग का नाम

क.	पदनाम	विभाग के अंतर्गत संस्थाओं में कुल दैनिक वेतनभोगी/ अस्थाई/ संविदा नियुक्तियों की संख्या	कॉलम (3) में 10 वर्ष से अधिक की अवधि से निरन्तर कार्यरत की संख्या	समिति द्वारा नियमितीकरण हेतु उपयुक्त पाये गये प्रकरणों की संख्या	नियमितीकरण हेतु शेष बचे कर्मचारियों की संख्या. (कॉलम नं. 3–4)
1.	2.	3.	4.	4.	5.

अधिकारी का नाम एवं पदनाम

शाकेमुभो—223—विकअसाप्रवि—17-5-07—1000.